

प्रेषक,

कुंवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक: 21 दिसम्बर, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजनागत पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर जनपद-देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक: 6483/डीटीईयू/भवन/0405/विकासनगर/2007, दिनांक: 22 अगस्त, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर, देहरादून के भवन निर्माण हेतु प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आंगणन रुपये 71.60 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रुपये 62.93 लाख के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 9,73,209 /- की धनराशि शासनादेश संख्या : 262/VIII/05-721-प्रशि0/2004, दिनांक 31 मार्च, 2005 एवं रुपये 20,00,000/- की धनराशि शासनादेश संख्या 464/VIII/05-721-प्रशि0/2004, दिनांक 3 मार्च, 2006 द्वारा इस प्रकार कुल रुपये 29,73,209/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 22 अगस्त, 2007 के कम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विकासनगर के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण किये जाने हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में संस्तुत आंगणन के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 33,19,791/- (रुपये तैंतीस लाख उन्नीस हजार सात सौ इक्यानब्बे मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4- स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो।



व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

- 5- शासनादेश संख्या : 262/VIII/07-721-प्रशि0/2004, दिनांक 31 मार्च, 2005 में उल्लिखित प्रस्तर-4,5,6,7 तथा प्रस्तर-8 में अंकित समस्त शर्तें (1 से 8 तक) यथावत प्रभावी रहेंगी।
- 6- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- 7- कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 8- उक्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन, 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-आयोजनागत-00 के सुसंगत मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 1163/XXVII(5)/2006, दिनांक: 24-दिसम्बर, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुंवर सिंह)

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1559(1)/VIII/07-721-प्रशि0/2004, तददिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- प्रबन्धक निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- वित्त अनुभाग-5
- 9- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

अनुसचिव।